प्रेस विज्ञप्ति

09/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 08.10.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत केरल और तमिलनाडु में 17 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उच्च-स्तरीय विदेशी वाहनों के अवैध आयात और संबंधित अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़े एक मामले के संबंध में की गई।

प्रारंभिक जानकारी में मेसर्स शाइन मोटर्स के साझेदारों, साथिक बाशा और इमरान खान के नेतृत्व वाले कोयंबटूर स्थित एक नेटवर्क की पहचान की गई है। दोनों ने कथित तौर पर जाली अनापत्ति प्रमाणपत्रों का उपयोग करके भूटान से पुराने वाहन खरीदे और अनधिकृत माध्यमों से भुगतान किया।

एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर स्थित 17 स्थानों - आवासों, कार्यशालाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और चेन्नई स्थित एक पते पर एक साथ तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन के कागजात और भुगतान रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए।

तलाशी के दौरान, सातिक बाशा और इमरान खान ने फेमा की धारा 37 के तहत बयान दिए, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 2023-24 के बीच उन्होंने भूटान से एक पूर्व सैन्यकर्मी, श्री शा किनले, जो भूटान के एक मध्यस्थ थे, के माध्यम से लगभग 16 वाहन खरीदे। वाहनों को जयगांव स्थित भारत-भूटान सीमा तक ले जाया गया, कार-वाहकों पर लादा गया और बिना सीमा शुल्क निकासी के कोलकाता, भुवनेश्वर और चेन्नई होते हुए कोयंबटूर पहुँचाया गया। कोई आयात शुल्क नहीं दिया गया। वाहनों को तोड़कर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्पेयर पार्ट्स के रूप में बेचा गया, अक्सर ओएलएक्स और इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नकद या व्यक्तिगत खातों में भुगतान के साथ। इनमें से किसी भी फर्म के पास आयात-निर्यात कोड नहीं था, न ही कोई वैधानिक चालान बनाए रखा गया था।

केरल भर में गैरेज और वर्कशॉप की तलाशी में वाहनों के टूटे हुए पुर्जे और भूटान स्थित आपूर्तिकर्ताओं के साथ संचार के डिजिटल साक्ष्य मिलने की पुष्टि हुई है। ज़ब्त की गई सामग्री में जाली अनापत्ति प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप चैट, बैंक विवरण और खरीदारों की सूचियाँ शामिल हैं।

जाँच में प्रथम दृष्टया विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1999 की धारा 3, 4 और 8 का उल्लंघन सामने आया है, जो अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन और विदेशी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है। ज़ब्त किए गए रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है ताकि धन के लेन-देन का पता लगाया जा सके और विदेशी खातों की संलिप्तता की पुष्टि की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय सत्यापन और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क, राज्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है।

इस अभियान ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफ़ाश किया है जो सीमा शुल्क से बचने और अनौपचारिक माध्यमों से विदेशी मुद्रा की तस्करी के लिए छिद्रपूर्ण सीमाओं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग करता था। तलाशी के दौरान प्राप्त स्वीकारोक्ति ने धन का पता लगाने और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए हैं। ईडी भारत की वित्तीय प्रणाली को कमजोर करने वाले हवाला लेनदेन, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और सीमा पार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

मामले में आगे की जाँच जारी है।